Unit-1

कृषि विकास के मॉडल

1. फिजियोक्रेट्स का नजरिया (Physiocrats' Approach)

फिजियोक्रेट्स 18वीं सदी के फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों का एक समूह था, जिन्होंने माना था कि कृषि ही राष्ट्र की असली संपत्ति है. उनका मानना था कि जमीन और उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद ही असली धन स्रोत होते हैं, उद्योग या व्यापार नहीं.

आइए उनके दृष्टिकोण के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखें:

- **भूमि सर्वोपरि :** फिजियोक्रेट्स का मानना था कि केवल भूमि ही वह स्रोत है जो नया मूल्य पैदा कर सकती है. उद्योग और व्यापार केवल पहले से मौजूद मूल्य को रूपांतरित करते हैं. उदाहरण के लिए, कपास उगाना मूल्य का सृजन है, जबकि कपास से कपड़ा बनाना मूल्य का रूपांतरण है.
- **कृषि कर :** फिजियोक्रेट्स एकल भूमि कर (Single Land Tax) के पक्षधर थे. उनका मानना था कि सरकार को सिर्फ कृषि उपज पर ही कर लगाना चाहिए, ना कि उद्योगों या व्यापार पर. यह कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता.
- **लेसेज़-फेयर (Laissez-faire):** फिजियोक्रेट्स कम से कम सरकारी हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास रखते थे. उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था प्राकृतिक नियमों के अनुसार बेहतर चलती है. सरकार को बाजार में कम से कम दखल देना चाहिए और व्यापार को स्वतंत्र रूप से चलने देना चाहिए.
- **मुक्त व्यापार (Free Trade):** फिजियोक्रेट्स मुक्त व्यापार के समर्थक थे. उनका मानना था कि देशों को बिना किसी रोक-टोक के एक-दूसरे के साथ व्यापार करना चाहिए. इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और सभी देशों को लाभ होगा.

आलोचना (Criticism):

फिजियोक्रेट सिद्धांत की कई आलोचनाएँ भी हुई हैं. आलोचकों का कहना है कि उनका सिद्धांत उद्योग और व्यापार के महत्व को कम आंकता है. साथ ही, यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि कृषि से प्राप्त कर को किस प्रकार से वसूलना चाहिए. हालांकि, फिजियोक्रेटों के विचारों ने आधुनिक अर्थशास्त्र को प्रभावित किया है. उनकी सरकार के कम हस्तक्षेप और मुक्त बाजार की वकालत ने आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है.

2. W.A. लुईस मॉडल (W.A. Lewis Model)

W.A. लुईस मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक आर्थिक विकास का मॉडल है, जिसे अर्थशास्त्री सर आर्थर लुईस द्वारा प्रस्तावित किया गया था. यह मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है कि विकासशील देशों में आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक श्रम होता है, जिसे "अधिशेष श्रम" (Surplus labour) कहा जाता है. लुईस मॉडल यह बताता है कि कैसे यह अधिशेष श्रम आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकता है. आइए देखें इसके प्रमुख बिंदु:

- **अधिशेष श्रम (Surplus labour):** लुईस का मानना था कि विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र इतना अधिक उत्पादक हो सकता है कि कम श्रमिकों के साथ भी वही उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है. अतिरिक्त श्रमिक "अधिशेष श्रम" कहलाते हैं, जिनकी कृषि में उत्पादकता कम होती है.
- **श्रम का अंतरण (Transfer of Labour):** लुईस का सुझाव है कि इस अधिशेष श्रम को कृषि से निकालकर उद्योग क्षेत्र में स्थानांतरित (Shift) किया जाए. नये उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ये श्रमिक अपनी आय से मांग को बढ़ाएंगे.
- **मजदूरी दरें (Wage rate):** मॉडल यह मानता है कि कृषि क्षेत्र में मजदूरी दरें निर्वाह मजदूरी (Subsistence wage) के बराबर होती हैं. इसका मतलब है कि किसान परिवार सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक आय ही कमाते हैं. उद्योगों में मजदूरी दरें कृषि से थोड़ी अधिक हो सकती हैं.
- **पूंजी निर्माण (Capital formation):** उद्योगों से होने वाले मुनाफे का उपयोग नये उद्योगों की स्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा सकता है. इससे पूंजी का निर्माण होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी.

मॉडल की सीमाएं-

- लुईस मॉडल यह नहीं बताता कि नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी कहां से आएगी.
- यह मॉडल कृषि उत्पादकता में सुधार पर ध्यान नहीं देता है.
- मॉडल यह मानता है कि श्रम का स्थानांतरण सुचारू रूप से होगा, जो वास्तविकता में हमेशा संभव नहीं होता.

हालांकि, अपनी सीमाओं के बावजूद, W.A. लुईस मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रदान करता है. यह बताता है कि कैसे श्रम का कुशल आवंटन और औद्योगिक विकास आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं.

3. फी-रानिस मॉडल (Fei & Ranis Model)

फी-रानिस मॉडल, जिसे अधिशेष श्रम मॉडल (Surplus Labour Model) के रूप में भी जाना जाता है, W.A. लुईस मॉडल का एक विस्तार है. अर्थशास्त्रियों जॉन सी. एच. फी और गुस्ताव रानिस द्वारा प्रस्तुत यह मॉडल लुईस मॉडल की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास करता है.

आइए देखें फी-रानिस मॉडल की प्रमुख विशेषताएं:

- **दोहरी अर्थव्यवस्था (Dual Economy):** यह मॉडल अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है- परम्परागत कृषि क्षेत्र (Traditional agriculture sector) और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र (Modern Agriculture sector). कृषि क्षेत्र में अत्यधिक श्रम होता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी और प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग होता है.
- **अधिशेष श्रम का क्रमिक स्थानांतरण-** फी और रानिस लुईस मॉडल के विपरीत यह मानते हैं कि श्रम का स्थानांतरण धीरे-धीरे होगा. कृषि क्षेत्र से श्रमिक तभी बाहर निकलेंगे जब उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादक रोजगार के अवसर मिलेंगे.
- **कृषि विकास का महत्व-** फी-रानिस मॉडल कृषि क्षेत्र के विकास पर भी बल देता है. उनका मानना है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के लिए श्रमिकों की आपूर्ति भी बनी रहेगी. बढ़ती कृषि आय औद्योगिक उत्पादों की मांग भी बढ़ाएगी.
- **पूंजी निर्माण-** फी और रानिस मॉडल में भी पूंजी निर्माण पर ध्यान दिया जाता है. औद्योगिक मुनाफे और बचत को नए उद्योगों की स्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास में लगाया जा सकता है.

मॉडल की सीमाएं

- फी-रानिस मॉडल भी यह नहीं बताता कि नए उद्योगों की स्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरुआती पूंजी कहां से आएगी.
- मॉडल यह मानता है कि सरकार की भूमिका सीमित होनी चाहिए, जबकि वास्तविकता में सरकार को बाजार विफलताओं को दूर करने और पूंजी निर्माण में सहायता करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

हालांकि, अपनी सीमाओं के बावजूद फी-रानिस मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृषि और उद्योग के एकीकृत विकास के महत्व को रेखांकित करता है. यह मॉडल यह बताता है कि कैसे श्रम का कुशल आवंटन, पूंजी निर्माण और कृषि तथा उद्योग का संतुलित विकास आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकता है.

4. कृषि विकास का शूल्ज सिद्धांत (Krishi Vikas ka Schultz Siddhant)

थियोडोर डब्ल्यू. शूल्ज अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पारंपरिक कृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया. उनका मानना था कि विकासशील देशों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों में मानवीय पूंजी (Human capital) का निवेश करना सबसे महत्वपूर्ण है. आइए उनके सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं को देखें:

- **किसान आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं-** शूल्ज इस बात से सहमत नहीं थे कि पारंपरिक किसान अकुशल होते हैं. उनका मानना था कि किसान अपने सीमित संसाधनों के आधार पर बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं.

- **मानवीय पूंजी का महत्व-** शूल्ज का मुख्य तर्क यह था कि विकासशील देशों में कृषि विकास के लिए किसानों में शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं के माध्यम से मानवीय पूंजी का निवेश करना चाहिए. शिक्षित किसान नई तकनीकों को सीख सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और नवाचार कर सकते हैं.
- **अनुसंधान और विस्तार सेवाएं-** शूल्ज ने अनुसंधान पर बल दिया जिससे नई किस्मों के बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीकों का विकास हो सके. साथ ही, विस्तार सेवाओं के माध्यम से इन नई तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए.
- **भौतिक पूंजी का पूरक-** शूल्ज ने भौतिक पूंजी (Physical capital) जैसे सिंचाई प्रणालियों, उर्वरकों और ट्रैक्टरों के महत्व को नकारा नहीं था. लेकिन उनका मानना था कि मानवीय पूंजी के बिना भौतिक पूंजी का प्रभाव सीमित होता है. शिक्षित किसान ही इन पूंजी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं.

आलोचना-

- शूल्ज के सिद्धांत की आलोचना की गई है कि यह भूमि सुधारों और सामाजिक असमानता को नजरअंदाज करता है. भूमिहीन किसानों या छोटे जोत वाले किसानों के लिए नई तकनीकों को अपनाना मुश्किल हो सकता है.
- आलोचकों का यह भी कहना है कि शूल्ज का सिद्धांत केवल उन किसानों के लिए कारगर हो सकता है जिनके पास पहले से ही कुछ पूंजी या संसाधन हों. गरीब किसानों के लिए ऋण प्राप्त करना या नई तकनीकों को अपनाना कठिन हो सकता है.

हालांकि, अपनी सीमाओं के बावजूद, शूल्ज का सिद्धांत कृषि विकास के लिए मानवीय पूंजी के महत्व को रेखांकित करता है. शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों का कौशल विकास कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

5. जॉर्जेंसन का द्वि-क्षेत्रीय मॉडल (Jorgenson's Dual-Economy Model)

डेल जॉर्जेंसन द्वारा प्रस्तुत द्वि-क्षेत्रीय मॉडल (Dual Economy Model) कृषि अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है. यह मॉडल पारंपरिक लुईस मॉडल और फी-रानिस मॉडल से अलग है, आइए देखें इसके प्रमुख बिंदुओं को:

- **दो क्षेत्रों का विभाजन-** जॉर्जेंसन का मॉडल भी अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है - कृषि क्षेत्र और आधुनिक उद्योग क्षेत्र.
- **परिवर्तनशील मजदूरी दरें-** लुईस मॉडल के विपरीत, जॉर्जेंसन का मॉडल यह मानता है कि दोनों क्षेत्रों में मजदूरी दरें लचीली होती हैं अर्थात्, श्रम की आपूर्ति और मांग के अनुसार मजदूरी दरें बदल सकती हैं.
- **तकनीकी प्रगति-** जॉर्जेंसन का मॉडल कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति (Technical Progress) पर बल देता है. इसका मतलब है कि नए बीजों, उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है.
- **श्रम का अंतरण-** कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति से श्रम की मांग कम हो सकती है. अतिरिक्त श्रमिक तब आधुनिक उद्योग क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकते हैं, जहाँ उनकी उत्पादकता अधिक होती है. यह स्थानांतरण मजदूरी दरों में अंतर के कारण होता है.
- **पूंजी निर्माण-** आधुनिक उद्योग क्षेत्र में मुनाफे का उपयोग नए उद्योगों की स्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा सकता है. इससे पूंजी का निर्माण होगा और दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी.

मॉडल की सीमाएं

- जॉर्जेंसन का मॉडल यह नहीं बताता कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को कैसे प्रोत्साहित किया जाए.
- मॉडल यह मानता है कि बाजार श्रम का कुशल आवंटन करता है, लेकिन वास्तविकता में बाजार विफलताएं हो सकती हैं.
- मॉडल सामाजिक असमानता और भूमि सुधारों जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं करता है.

हालांकि, अपनी सीमाओं के बावजूद, जॉर्जेंसन का द्वि-क्षेत्रीय मॉडल कृषि विकास के लिए प्रासंगिक है. यह मॉडल इस बात पर प्रकाश डालता है कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और श्रम का कुशल आवंटन आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं.